जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 18 संख्याः 162 प्रभात चूरू, गुरूवार 8 अक्टूबर, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'ज्ञानेश कुमार कहाँ मिलेगा, मोदी जी की गोदी में'

वैसे तो नारों का स्तर गिरता ही है, धरने-प्रदर्शनों में, पर, प्रियंका जी का यह नारा, अपनी गिरावट के कारण काफी समय तक याद रहेगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। राहुल और प्रियंका के लिए सैंट्रल दिल्ली की सड़कों पर यह दूसरा दिन था। विपक्ष के नेताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सरकार ने हिरासत और बड़े पैमाने पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनपथ स्थित सागर रत्ना में विपक्षी सांसदों के लिए लंच का आयोजन किया।

लंच के बाद विपक्षी सांसद जंतर-मंतर जाना चाहते थे और वहां धरना देना चाहते थे। उनका कहना था कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन के लिए वही जगह तय की है।

सांसद बसों में सवार हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर तक जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि, वहां कई बैरीकेड्स लगे थे और बड़ी संख्या में पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात थे।

जंतर-मंतर पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई थी और विपक्षी सांसदों को वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई।

- प्रियंका जी ने जब यह नारा लगाया, वे मैरीडियन होटल के ''राउन्डअबाउट'' के पास जमीन पर लेटी थीं तथा उनके हाथ में संविधान की एक कॉपी थी तथा राहुल गांधी उनक पास मंडरा रहे थे, पुलिस को प्रियंका जी को घसीट कर बस में ले जाने से रोकने के लिए।
- इससे पूर्व कांग्रेसाध्यक्ष ने रेस्टोरेन्ट, सागर रत्ना में, विपक्ष के सांसदां का लंच रखा था, धरने-प्रदर्शन की आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए।

इसके बाद विपक्षी सांसद मेरिडियन होटल के गोलचक्कर के पास सड़क पर ही बैठ गए। पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा था।

बाद में राहुल और प्रियंका को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का बड़ा दल वहां पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी और शाह ने दोनों भाई-बहन को गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस मशीनरी लगा दी हो।

दोनों ने पूरी ताकत के साथ इसका विरोध किया।

प्रियंका सड़क पर लेटी हुई थीं, नारे लगा रही थीं और उनके हाथ में संविधान की एक प्रति थी। राहुल गांधी उन्हें सुरक्षा देने के लिए उनके आस-पास मंडरा रहे थे, ताकि पुलिस उन्हें घसीटकर बस में न ले जा सके।

राहुल और प्रियंका को बस में बैठाने की जद्दोजहद काफी देर तक चली। आखिरकार सूर्यास्त के आसपास दोनों को खींचकर पुलिस बस में बैठा दिया गया।

एक बार फिर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया और लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

राहुल और प्रियंका ने सड़क पर उतरकर निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूँक दी है और उसे एक मजबूत ताकत बना दिया है। इससे पहले पार्टी केवल ट्वीट के जरिए अपना विरोध दर्ज कराने तक सीमित दिखाई देती थी।

कांग्रेस ने 7 अक्टूबर को ''काला दिवस'' घोषित किया है और पूरे देश में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है।

कल आकाशवाणी भवन में धरना देने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले से ही 45 एफ.आई.आर. दर्ज हैं 100 एफ.आई.आर. के साथ उनका लक्ष्य ''शतक'' बनाने का है।

बिना डरे और बिना पीछे हटे उन्होंने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने साफ कहा कि है कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा और मोदी उनका इस्तीफा सुनिश्चित करेंगे।

बराखंभा पुलिस थाने में, जहां कांग्रेस नेताओं को ले जाया गया था, प्रियंका और अन्य नेताओं ने कहा: ''ज्ञानेश कुमार कहां मिलेगा? मोदीजी की गोद में।''

मुहाना थाने में युवक की मौत की जाँच मानवाधिकार आयोग खुद करेगा

जयपुर, 7 अक्टूबर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने शहर के मुहाना थाने में पुलिस की कथित मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले की स्वयं जांच करना तय किया है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने

- आयोग ने अपने आईजी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जाँच की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

आयोग के आईजी हिंगलाज दान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संध्या यादव को कहा है कि वे स्वयं के स्तर पर घटना की जांच करें और तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें। आयोग ने दोनों अफसरों को कहा है कि वे घटना के गवाहों, चिकित्सकों से साक्ष्य लेकर मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर उसकी जांच करें। इसके साथ ही, घटना के दिन से एक सप्ताह पहले तक की सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र करें। आयोग ने कहा कि आज प्रकाशित खबर के अनुसार, अवैध कस्टडी में युवक को टॉर्चर किया गया, जिससे दिमाग में चोट से उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस ने झूठ छिपाने के लिए उसे अस्पताल ले जाकर एंटीवेनम के दस इंजेक्शन लगवाकर 96 हजार रुपए का बिल भी भरा। खबर में यह भी बताया गया कि सांप डसने की कहानी रची गई, लेकिन जांच में एक भी निशान नहीं मिला। इसके अलावा खबर में दो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयुक्त ने सांसदों से नहीं मिल पाने के कारण गिनाए

चुनाव आयुक्त के अनुसार, शाम चार बजे तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात के लिए अर्जी नहीं दी थी, अतः मुलाकात कैसे जी जा सकती थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। इंडिया गठबंधन के सांसदों के चुनाव आयोग की ओर मार्च करने और पूरे दिन विरोध प्रदर्शन करने के कुछ घंटे बाद, चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम को कहा कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने कहा कि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलना चाहता है और एक ज्ञापन सौंपना चाहता है।

- शाम को चार बजे चुनाव आयोग को सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी उनके मिलना चाहते हैं।
- चुनाव आयुक्त के अनुसार, दिल्ली पुलिस से उन्हें सूचना मिली कि 240 सांसदों का ग्रुप उनसे मिलने आ रहा है, इस पॉर्लियामैंट हाउस की एनेक्सी में।
- चुनाव आयुक्त ने इस पर कहा कि स्थापित परम्परा के अनुसार, चुनाव आयुक्त के परिसर में ही मुलाकात हो सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं।
- अतः चुनाव आयुक्त ने अपना एक उच्चाधिकारी, इन सांसदों से मिलने के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया, जिसे सांसदों ने ''रिजैक्ट'' कर दिया।

आयोग ने कहा कि उसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ राजनीतिक दलों के आयोग मुख्यालय की ओर मार्च के दौरान, कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे।

आयोग ने एक बयान में कहा, ''आज शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था।''

शाम करीब 4 बजे आयोग को दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है और एक ज्ञापन सौंपना चाहता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाँग्लादेश के प्र.मंत्री बार-बार भारत यात्रा क्यों टाल रहे हैं?

प्र.मंत्री बनने के बाद वे मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब व टर्की की राजकीय यात्रा कर चुके हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार की प्रक्रिया लगातार रुकी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान लंबे समय से प्रस्तावित अपनी भारत यात्रा को बार-बार टाल रहे हैं। नवंबर या दिसंबर में संभावित यात्रा की तारीख अभी भी तय नहीं हुई है।

फरवरी 2026 में बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में काफी गिरावट आई है।

शेख हसीना की पिछली अवामी लीग सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी मजबूत थे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, संपर्क और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग हुआ था। जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया, उन्हें भारत भागना पड़ा

- पर, बाँग्लादेश के प्र.मंत्री तारिक रहमान, भारत से कुछ चौंकन्ने हैं तथा ''सबसे पहले बाँग्लादेश ही रहेगा'', इस नारे के तहत, बाँग्लादेश की सार्वभौमिकता, बराबरी व गैर हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करते हुए, भारत द्वारा आयोजित ''ब्रिक्स सम्मेलन'' में भी नहीं आए।

और बाद में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे पूरी स्थिति ही बदल गई।

बीएनपी का रुख ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रभाव को लेकर अधिक सतर्क रहा है। पार्टी ने ''बांग्लादेश फर्स्ट'' विदेश नीति अपनाई है, जिसमें देश की संप्रभुता, समानता और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया है। तारिक रहमान ने मलेशिया, चीन, जापान, सऊदी अरब और तुर्किए की यात्राओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निमंत्रण के बावजूद हिस्सा नहीं लिया। इससे संकेत मिलता है कि बांग्लादेश जानबूझ भारत-केन्द्रित नीति से अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुद्दा शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर है। ढाका लगातार इस मामले में प्रगति चाहता है। बांग्लादेश ने 2013 की द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत, उनकी वापसी की औपचारिक मांग की है, ताकि वे नवंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई मौत की सजा का सामना कर सकें। यह सजा 2024 के आंदोलन के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों के लिए सुनाई गई थी।

शेख हसीना ने स्वयं भी कई बार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरसीए प्रकरण की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को

जयपुर, 7 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को आरसीए चुनाव से जुड़े मामले में लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत इस मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

राजीव प्रताप सिंह की यह जनहित याचिका बुधवार को जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई थी,

- इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय थी।

लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ गठित नहीं हुई। इस पर प्रकरण जस्टिस महेन्द्र गोयल और भुवन गोयल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा, जहां अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है। जनहित याचिका पर पूर्व में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एडहॉक कमेटी को भंग कर आईएएस भास्कर ए. सांवत को प्रशासक नियुक्त कर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी थी। वहीं, गत 29 सितंबर को चुनाव हुए, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी।

आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रैपो रेट बढ़ाई

रैपो रेट से मतलब है, वह ब्याज दर, जो आरबीआई चार्ज करती है, व्यवसायिक बैंकों से अल्पकालीन ऋणों पर

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। आरबीआई के रैपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (0.25 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के फैसले से यह दर 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गई है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज लेना थोड़ा महंगा हो जाएगा।

रैपो रेट वह दर है, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम अवधि के लिए पैसा उधार देता है। जब आरबीआई इसे बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए पैसे की लागत बढ़ने लगती है। इसके बाद बैंक कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा सकते है, जिससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और कारोबार के लिए मिलने वाला कर्ज महंगा हो सकता है।

इसका उद्देश्य मांग को इतना कम करना है कि महंगाई लंबे समय तक बनी न रहे। ऊंची ब्याज दरें नए कर्ज और निवेश को कम कर सकती हैं, बचत को बढ़ावा दे सकती हैं और आखिरकार कीमतों पर दबाव कम कर सकती हैं।

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण

- इस रैपो रेट के बढ़ने से, बैंकों से चार्ज किए जा रहे ब्याज दर में भारी परिवर्तन होगा।
- आरबीआई का इतनी थोड़ी सी रेट बढ़ाने का मतलब है, बैंकिंग इण्डस्ट्री को मैसेज देना कि आरबीआई महंगाई (इनफ्लेशन) के बारे में संवेदनशील है और अगर महंगाई पर नियंत्रण हासिल नहीं हुआ तो आरबीआई कुछ ''ग्रोथ'' का बलिदान भी कर सकती है, महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए।

है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि आरबीआई महंगाई के हालात को लेकर पहले की तुलना में कम आश्वस्त है। अगर आर्थिक विकास की दर अच्छी बनी हुई है और महंगाई बढ़ रही है, तो केन्द्रीय बैंक के पास बहुत उदार मॉनिटरी पॉलिसी बनाए रखने की वजह कम हो जाती है।

आरबीआई के लिए समस्या केवल मौजूदा महंगाई की दर नहीं है, बल्कि इस बात की आशंका भी है कि ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें, कच्चा तेल, कमोडिटी की कीमतें, मजदूरी और ग्लोबल सप्लाई में रुकावटें, ये सभी महंगाई को और बड़ा सकते हैं।

इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अगर परिवारों और बिज़नैस को लगने लगे कि कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, तो वे अपनी खरीदारी जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा वेतन की मांग कर सकते हैं या खुद अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं। इससे महंगाई को नियंत्रित करना और मुश्किल हो सकता है।

इसलिए ब्याज दर बढ़ाने का एक उद्देश्य महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदों को स्थिर करना भी है।

इसका सबसे सीधा असर उन कर्ज लेने वालों पर सबसे ज्यादा दिखेगा, जिनके लोन फ्लोटिंग या एक्स्टर्नल बैंचमार्क दरों से जुड़े हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपये का फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया है और बैंक पूरी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का बोझ ग्राहक पर डाल देता है, तो उसके ब्याज का खर्च बढ़ सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है, ब्याज दर कब और कैसे बदली जाती है, लोन की कितनी अवधि बाकी है और बैंक क्या फैसला करता है।

मौजूदा फिक्स्ड रेट वाले कर्ज लेने वालों पर आमतौर पर इसका तुरंत असर नहीं पड़ेगा।

जमाकर्ताओं को इस बढ़ोतरी का फायदा हो सकता है। बैंकों के बीच जमा राशि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य ब्याज देने वाले उत्पादों पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। आरबीआई के सामने एक मुश्किल संतुलन बनाए रखने की चुनौती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी आडवाणी से मिलने उनके घर गये

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके

- उन्होने कहा कि आडवाणी के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन ने स्थायी छाप छोड़ी है।

आवास पर मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने आडवाणी जी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आडवाणी के दशकों लंबे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड बनाएगी- पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि सांसदों को निर्वाचन आयोग से मिलाने के स्थान पर थाने ले जाया गया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 7 अक्टूबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने राजस्थान के पंचायतीराज चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, इस बार पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तथा अच्छे और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा।

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पंचायत चुनाव लड़ेगी तथा अच्छे, साफ छवि वाले व युवाओं को टिकट दिया जाएगा।

युवाओं को भी चुनाव में मौका देने पर जोर रहेगा। पायलट ने ये बातें बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के वॉर रूम में मीडिया से रूबरू होकर कहीं।

इससे पहले पायलट ने एआईसीसी राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में आयोजित कैंपेन कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पंचायतीराज चुनावों के प्रचार, प्रत्याशी चयन, संगठन को राजस्थान में सक्रिय करने समेत कई मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई।

सचिन पायलट ने कहा कि आगामी पंचायतीराज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले अंतिम बड़ा चुनाव पंचायतों का है। पार्टी ने जिलों की स्थिति पर चर्चा कर, चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तय की है।

निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा जीतकर भी हार गई और कांग्रेस हारकर भी जीती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कई जिलों से शिकायतें मिलीं और पुलिस-प्रशासन के माध्यम से पार्षदों पर दबाव बनाने के प्रयास किए गए। आज कांग्रेस की बैठक में एक-एक जिले की स्थिति पर चर्चा की गई है।

निर्वाचन आयोग को लेकर सचिन पायलट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसदों के साथ हुए व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करीब 250-300 सांसद निर्वाचन आयोग प्रमुख से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बसों में भरकर थाने भेजा गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और सवाल पूछना सांसदों का अधिकार है। उन्होंने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस अगले 2 माह तक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और कथित अनियमितताओं को जनता के सामने रखेगी। पायलट ने कहा कि संविधान ने नागरिकों को मताधिकार दिया है और लोकतंत्र में इस अधिकार की रक्षा जरूरी है।

सीजेपी का आंदोलन 10 अक्टूबर से जंतर-मंतर पर होगा

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता

- सीजेपी ने घोषणा की कि चुनाव व्यवस्था में सुधार के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा।

सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसी मांगों को लेकर 10 अक्टूबर को यहां के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और एआईएसए की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)